साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 18 | अंक 02 | प्रति सोमवार इंदौर, 12 अगस्त से 18 अगस्त 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

पड़ोसी बांग्लादेश की आग में मोदी की चुप्पी

बांग्लादेश में हिंदूओं के कत्लेआम पर भाजपा-संघ का मौन क्यों?

अखिल हिंदू राष्ट्र की नौटंकी, देश व विदेशों में हिंदुओं पर होते अत्याचार, बर्बादी 15 करोड़ की अकाल मृत्यु, समाप्ति का षड्यंत्र

देश में छल, बल, दल व झूठे वादों की वाचालता से सन 2014 में सत्ता हथियाने के बाद देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और पूंजीपतियों के इशारे पर नाच उनके मोटे लाभ के लिए सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी से 40 करोड़ हिंदुओं को बेरोजगार बनाने के साथ कोरोना के नाम पर जबरदस्ती टीका ठोक 15 करोड़ हिंदुओं को कालमौत देकर हिंदुओं को हर तरह तबाह किया गया।

अखिल हिंदू राष्ट्र की भूखेरा जन पार्टी और उसकी 1930 से अभी तक देश भक्ति परंपरा संस्कृति की अफीम पिलाकर घोर शोषण करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न केवल इस प्रकार से देश में हिंदुओं का शाखाओं के माध्यम से एकत्रित कर छल बल दल का प्रदर्शन कर भ्रमित कर सट्टा हथियाने में तो सफल हो ही गई औल सत्ता हथियाने के बाद यथार्थ में सबसे ज्यादा बर्बादी उसने हिंदुओं की ही की। पड़ोसी देशों बांग्लादेश पाकिस्तान मैं रहने वाले हिंदूओ के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है जबकि मोदी के आने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से ही न केवल व्यापार हो रहा है। हजारों करोड़ की बिजली आपूर्ति का मोटी कमाई की जा रही है। और राजनीतिक संबंध होने के उपरांत भी मोदी कभी किसी से हिंदुओं की सुरक्षा की बात और मांग नहीं करता। बांग्लादेश और पाकिस्तान सर्व धर्म सौहाद्र की बात भर करते हैं। परंतु दोनों ही रास्ते में हिंदुओं के साथजातियां वहां के मुसलमान करते रहते हैं और यह बात विश्व स्तर पर जानी जाती है।

मोदी अपनी विदेश यात्राओं में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान जहां-जहां भी गए अपने मित्रों अडानी अंबानी के लिए व्यापार के लिए उनके व्यावसायिक प्रतिनिधि बनकर गए। और राजनीतिक संबंधों का फायदा उठा अपने मित्रों के लिए व्यवसाय की व्यवस्था की। वर्तमान में अडानी विद्युत की आपूर्ति करता है तो अंबानी केजी बेसिन 6 की गैस की आपूर्ति पिछले 26 सालों से कर रहा है। उनके व्यापार के चलते हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के बारे में मोदी उसका पूरा मंत्रिमंडल के साथ राष्ट्रीय स्वयं स्वयंसेवक संघ भी चुपचाप बैठा हुआ है। उसके पीछे का सच

भारत-बांग्लादेश को लगभग 1.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है..बांग्लादेश भारत का अहम

'ट्रेडिंग पार्टनर' है..कुछ मिसालों के साथ बताता हूँ ताकि दिमाग़ का कचरा साफ़ हो सके..

पीएम नरेंद्र के परम पूजनीय अदाणी का बहुत बड़ा व्यापार बांग्लादेश में है..बिजली से खाने का तेल तक बहुत बड़ी सप्लाई है..

भारत सरकार की कंपनियां NTPC, PFC, REC, PTC वग़ैरह बांग्लादेश से बड़ा पैसा कमाती हैं..

1. Marico Ind : भारत की इस FMCG कंपनी की लगभग 15% कमाई बांग्लादेश से आती है..

2. पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज : फैशन कंपनी.. बांग्लादेश में बड़ी फैक्ट्री वग़ैरह है..

3. इमामी : भारत की इश्ण्ड कंपनियों में सब से बड़ा बांग्लादेशी एक्सपोज़र है..रियल एस्टेट में भी काम करती है..

(शेष पेज 6 पर)

घोर स्वार्थी जाहिल ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे व मोटे लाभ के लिये

देश की कृषि को खाद बीज बिजली की कीमत बढ़ा किया बर्बाद

भारत की खेती और किसान : दुनिया के सामने मोदी की डींग और धरती का सच

घोर स्वार्थी जाहिल गुजराती मोदी ने देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों व अपने पूंजीपति मित्रों के मोटे लाभ के लिए चारों तरफ देश में हर प्रकार की बर्बादी की जिसमें मुख्य बर्बादी कृषि की थी जिसे मोदी ने सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी के नाम पर भी न केवल भारत के तरीके से बर्बाद किया और दूसरी तरफ कृषि उपजों में आदानों की कीमतें बढ़ा, अनुदान खत्म या कम करके कृषि उत्पादन लागत को बढ़ा देश के लाखों किसानों को कृषि भूमि बेंचने या भारी कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। पिछले 10 वर्षों में सिर्फ अडानी, अम्बानी और 271 डॉलर अरबपति ही अपरम्पार समृद्ध नहीं हुए हैं, भाषा भी नयी-नयी व्यंजनाओं, रूपकों और मुहावरों से धनवान और मालामाल हुई है, यह तो मोदी जी का बड़प्पन है कि वे इस बात का कतई अभिमान नहीं करते कि उन्होंने किस तरह अब तक की प्रचलित, सार्वभौमिक और अब तक सर्वकालिक मानी जाने वाली उक्तियों को भी परिवर्धित कर दिया है। जैसे अब तक दुनिया यह मानकर बैठी थी कि झूठ केवल तीन तरह के होते हैं ; झूठ, सफ़ेद झूठ और आंकड़ों का झूठ!! पिछले 10 साल ने दुनिया की इस गलत और अधूरी धारणा को तोड़ दिया और इसमें झूठ के अब तक दो नए प्रकार और जोड़ दिए; एक आईटी सेल के दावे का परम झूठ, दूसरा मोदी जी की हांकी डींग का चरम झूठ। पिछली 2 अगस्त को नई दिल्ली में उन्होंने इसी चरम झूठ का परम प्रवाह किया और अन्तरराष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों के 6 दिन चलने वाले सम्मेलन में उन्होंने बिना इस बात की परवाह किये कि वे उन अर्थशास्त्रियों के बीच बोल रहे हैं जिनकी विशेषज्ञता ही इस क्षेत्र में है, भारत में कृषि के क्षेत्र में ऐसे दावों की झड़ी लगा दी – जो यथार्थ के आस-पास होना तो दूर की बात रही, उसके ठीक उलटे थे।

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

भारत के राष्ट्रध्वज की जीवन यात्रा

भारतीय पुरातन प्राचीन संस्कृति धर्म आध्यात्म और राजाओं के राजपाल के इतिहास में भी ध्वज का आत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। ध्वज का इतिहास मानव सभ्यता के साथ विकसित होने लगा था। इसके बारे में मैंने इतिहास खोजने की कोशिश विकिपीडिया पर भी की और उसके पास में भी कोई ध्वज का खास इतिहास नहीं है। जबकि धर्म शास्त्रों मेंयदि राम के कल को साढे चार लाख साल पुराना माना जाता है तो ध्वज का इतिहास व महत्व यथार्थ में वैदिक काल से था। हमारे मंदिरों पर ध्वज लगाने की प्रथा अनादि काल से है। वर्तमान भारत का राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास मार्च 116 साल पुराना है। 116 साल में छह बार बदला राष्ट्रीय ध्वज, जानें आजादी से पहले के पांच भारतीय झंडों की कहानी...

इस साल देश की आजादी को 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर पूरे हिंदुस्तान में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बीते 116 सालों में देश में छह बार झंडा बदला गया है। आजादी की वर्षगांठ पर हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज की इस यात्रा में क्या-क्या अहम पड़ाव रहे और कब-कब क्या-क्या बदलाव हुए। आखिरी बदलाव 1947 में हुआ था। आइए जानते हैं यूनियन जैक से तिरंगे तक का सफर ...

1906 में मिला पहला राष्ट्रीय ध्वज

भारत की आजादी की लड़ाई जैसे-जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने-अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। देश में पहला झंडा 1906 में सामने आया। सात अगस्त, 1906 को पारसी बागान चौक, कलकत्ता (अब ग्रीन पार्क, कोलकाता) में फहराया गया था। इस झंडे में तीन रंग की पट्टियां थीं। इनमें सबसे ऊपर हरे रंग, मध्य में पीले रंग और नीचे लाल रंग की पट्टियां थीं। इसमें ऊपर की पट्टी में आठ कमल के फूल थे, जिनका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वन्दे मातरम् लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज भी बने थे।

पहले ध्वज को मिले हुए एक साल ही हुआ होगा कि देश को दूसरा झंडा मिल गया। पहले पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भीकाजीकामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। यह झंडा भी देखने में काफी हद तक पहले जैसा ही था। इसमें केसरिया, पीला और हरे रंग की पट्टियां थी। बीच में वन्दे मातरम् लिखा था। वहीं, इसमें चांद और सूरज के सात आठ सितारे बने थे। इसके बाद 1917 में एक और नया झंडा सामने आया। डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने एक नया झंडा फहराया। इस नए झंडे में पांच लाल और चार हरे रंग की पट्टियां थी। झंडे के अंत की ओर काले रंग में त्रिकोणनुमा आकृति बनी थी। बाएं तरफ के कोने में यूनियन जैक भी था। जबकि एक चांद तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते सात तारे भी थे।

1921 में चौथी बार बदला देश का झंडा

इसके एक दशक बाद 1921 में ही भारत को अपना चौथा झंडा भी मिल गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान बेजवाड़ा (विजयवाड़ा) में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक झंडा दिया था, यह दो रंगों हरे और लाल रंग का बना हुआ था। गांधीजी ने इसमें कुछ बदलाव करवाए। उन्होंने इसमें सफेद, हरे और लाल रंग की तीन पट्टियां लगवाई थीं। वहीं, देश के विकास को दर्शाने के लिए बीच में बड़ा चलता हुआ चरखा भी बनाया गया था।

एक दशक बाद 1931 में फिर बदला राष्ट्रीय ध्वज

भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया। इस झंडे को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई गई। इसमें छोटे आकार पूरा चरखा बीच की सफेद पट्टी रखी गई थी। सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है।

आखिरकार 1947 में देश को मिला तिरंगा

तमाम प्रयासों के बाद जब 1947 में आखिरकार देश आजाद हुआ तो देश को तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई, 1947 में संविधान सभा की बैठक में भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्म चक्र को गहरे नीले रंग में दिखाया गया है। 24 तीलियों वाले चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं।

इसे पिंगली वैंकेया ने तैयार किया था। इसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी है। तीनों समानुपात में है। इसकी लंबाई - चौड़ाई दो बाय तीन है।

राष्ट्रभक्ति का पाखंड करने वाले

आरएसएस ने 1948 में तिरंगे को पैरों तले रौंदा

नागपुर के संघ मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता

भारतीय जनता पार्टी जो कि आरएसएस की और राजनीतिक शाखा है। कांग्रेस की तरह आरएसएस भी अंग्रेजों की राष्ट्रीय गोपनीय सेवा या नेशनल सिक्योरिटी सर्विस का हिंदी रूपांतरण था। जिसमें सारे दिग्गज हेडगेवार, गोलवलकर, विनायक दामोदर सावरकरन केवलउसके सदस्य थेवरुण अंग्रेजों से पेंशन भी लिया करते थे।

आज क्यों इतनी ज्यादा राष्ट्रप्रेम की बात करती है शायद इसलिए कि बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया था. 1930 और 1940 के दशक में जब आज़ादी की लड़ाई पूरे उफान पर थी तो आरएसएस का कोई भी आदमी या सदस्य उसमें शामिल नहीं हुआ था. यहाँ तक कि जहां भी तिरंगा फहराया गया आरएसएस वालों ने कभी उसे सैल्यूट तक नहीं किया. आरएसएस ने हमेशा ही भगवा झंडे को तिरंगे से ज्यादा महत्व दिया. 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गाँधी की हत्या कर दी गयी तो इस तरह की खबरें आई थीं कि आरएसएस के लोग तिरंगे झंडे को पैरों से रौंद रहे थे. यह खबर उन दिनों के अखबारों में खूब छपी थीं.

आज़ादी के संग्राम में शामिल लोगों को आरएसएस की इस हरकत से बहुत तकलीफ हुई थी. उनमें जवाहरलाल नेहरू भी एक थे. 24 फरवरी को उन्होंने अपने एक भाषण में अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था. उन्होंने कहा कि खबरें आ रही हैं कि आरएसएस के सदस्य तिरंगे का अपमान कर रहे हैं. उन्हें मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान करके वे अपने आपको देशद्रोही साबित कर रहे हैं.

यह तिरंगा हमारी आज़ादी के लड़ाई का स्थायी साथी रहा है,

जबकि आरएसएस वालों ने आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता की भावनाओं का साथ नहीं दिया था. तिरंगे की अवधारणा पूरी तरह से कांग्रेस की देन है. तिरंगे झंडे की बात सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश के मसुलीपट्टम के कांग्रेसी कार्यकर्ता पी वेंकय्या के दिमाग में उपजी थी. 1918 और 1921 के बीच हर कांग्रेस अधिवेशन में वे राष्ट्रीय झंडे को फहराने की बात करते थे. महात्मा गाँधी को यह विचार तो ठीक लगता था लेकिन उन्होंने वेंकय्या जी की डिजाइन में कुछ परिवर्तन सुझाए.

गाँधी जी की बात को ध्यान में रखकर दिल्ली के देशभक्त लाला हंसराज ने सुझाव दिया कि बीच में चरखा लगा दिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा. महात्मा गाँधी को लालाजी की बात अच्छी लगी और थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया. उसके बाद कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों में तिरंगा फहराया जाने लगा. अगस्त 1931 में कांग्रेस की एक कमेटी बनायी गयी, जिसने झंडे में कुछ परिवर्तन का सुझाव दिया. वेंकय्या के झंडे में लाल रंग था. उसकी जगह पर भगवा पट्टी कर दी गयी. उसके बाद सफ़ेद पट्टी और सबसे नीचे हरा रंग किया गया. चरखा बीच में सफ़ेद पट्टी पर सुपर इम्पोज कर दिया गया. महात्मा गाँधी ने इस परिवर्तन को सही बताया और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज अहिंसा और राष्ट्रीय एकता की निशानी है.

आज़ादी मिलने के बाद तिरंगे में कुछ परिवर्तन किया गया. संविधान सभा की एक कमेटी ने तय किया कि उस वक़्त तक तिरंगा कांग्रेस के हर कार्यक्रम में फहराया जाता रहा है लेकिन अब देश सब का है.

उन लोगों का भी जो आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के मित्र के रूप में जाने जाते थे. इसलिए चरखे की जगह पर अशोक चक्र को लगाने का फैसला किया गया. जब महात्मा गाँधी को इसकी जानकारी दी गयी तो उन्हें ताज्जुब हुआ. बोले कि कांग्रेस तो हमेशा से ही राष्ट्रीय रही है.

इसलिए इस तरह के बदलाव की कोई ज़रुरत नहीं है, लेकिन उन्हें नयी डिजाइन के बारे में राजी कर लिया गया. इस तिरंगे की यात्रा में बीजेपी या उसकी मालिक आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, लेकिन वह उसी के बल पर कांग्रेस को राजनीतिक रूप से घेरने में सफल होती नज़र आ रही है.

अजीब बात यह है कि कांग्रेस सहित सभी राजनितिक दल अपने इतिहास की बातें तक नहीं कर रहे हैं. अगर वे अपने इतिहास का हवाला देकर काम करें तो बीजेपी और आरएसएस को बहुत आसानी से घेरा जा सकता है और तिरंगे और देश भक्ति के नाम पर राजनीति करने से रोका जा सकता है।

वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरुरत, सवाल और धर्म के नाम पर चमकायी जा रही सियासत

एनडीए सरकार की तरफ से वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाया गया. हालांकि, लोकसभा में बवाल के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का फैसला किया गया है. कांग्रेस, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने इसका विरोध किया. जबकि, एनडीए की सहयोगी जेडीयू समेत कई राजनीतिक दलों ने इसके समर्थन में लोकसभा में अपनी बातें रखीं. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि ये बिल हिन्दू-मुसलमान में भेदभाव करने वाला है, ये बिल धार्मिक आजादी के खिलाफ है. उन्होंने तो मौजूदा एनडीए सरकार को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया.

कुछ इसी तरह के रिएक्शन इंडिया गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के रहे. समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि ये बिल सोची समझी राजनीति के तहत लाया जा रहा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड में आखिर गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है. चंद कट्टर समर्थकों के समर्थन के लिए ये बिल लाया जा रहा है.

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने जहां इसे वक्फ के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया, तो वहीं शरद पवार वाली एनसीपी का कहना है कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए. सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि इसे कम से कम स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि सरकार इस बिल पर इतनी जल्दबाजी में क्यों है और जब कोई ट्रिब्यूनल के खिलाफ कोर्ट जाएगा तो फिर उसका क्या महत्व रह जाएगा. फिलहाल, सरकार ने इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है.

वक्फ पर संशोधन की जरुरत या सियासत

सुप्रिया सुले ने ये सवाल किया कि डीएम को इतना अधिकार नए बिल में दिया जा रहा है, एकतरफा फैसला कलेक्टर कैसे ले सकता है. सेक्शन 40 क्यों डिलीट किया गया और उन्होंने आरोप लगाया कि बिल की कॉपी उन्हें पार्लियामेंट से नहीं बल्कि मीडिया से मिली. हालांकि, उनके इस आरोप को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खारिज कर दिया.

दरअसल, इन सभी चीजों पर गौर करने के बाद सवाल उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, कब-कब इसमें संशोधन हुआ और क्यों इसकी जरूरत पड़ी. हालांकि, राजनीति के जानकार और आईआईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार इस बारे में बताते हैं कि संशोधन वक्फ बोर्ड में कोई नहीं बात नहीं है, पहले भी संशोधन हुए हैं. उनका कहना है कि धर्म के नाम पर सियासत राजनेता न करें ये कैसे हो सकता है. लेकिन, ये सुधार की दिशा में एक बड़ा लॉ है क्योंकि डिफेंस और रेलवे के बाद देश में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ ही है.

वक्फ पर इससे आगे बढ़ने से पहले ये यहां पर जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ क्या है और इसको कब क्या अधिकार दिए गए. वक्फ का मतलब है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी संपत्ति जो किसी संस्था या व्यक्ति के नाम नहीं है.

वक्फ बोर्ड में संशोधन लाने के लिए भारत सरकार के पास बिल लाने का अधिकार है. आजाद भारत में इसमें कई बार सुधार हुए भी हैं. इसका गठन 1954 में हुआ. वक्फ बोर्ड में एक सर्वेयर होता है जो तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नही है. देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं और करीबन 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है. ये देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे अधिक जमीन रखने वाली संस्था है. वक्फ के ऊपर जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने, अतिक्रमण औ? भ्रष्टाचार का भी आरोप है. यहां तक कि केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने तो चर्चा के दौरान यह भी कहा कि वक्फ पर माफिया का कब्जा हो गया है.

इसका उद्देश्य ये भी था कि वक्फ के जरिए मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखा जाए ताकि इन जमीनों के गैरकानूनी ढंग से बेचने या उसके बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके. वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित में कई काम करता है.

क्यों उठ रहे सवाल

दरअसल, वक्फ बोर्ड में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान संशोधन किया गया. देशभर में वक्फ बोर्ड की तरफ से जहां भी घेरेबंदी कराया जाता है, उसके आसपान की जमीन भी अपनी प्रॉपर्टी करार देता है. इनमें आसपास की जमीनों और मजारों पर वक्फ का कब्जा हो जाता है.

1995 में नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया गया, उसमें इसे असीमित अधिकार दे दिए गए. उसके बाद अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन उसकी है तो उस संपत्ति के मालिक को ये साबित करना होगा कि ये उसकी है, वक्फ को ये साबित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. हालांकि, इस कानून में ये जरूर कहा गया कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन कई लोगों के पास पुख्ता प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं होते हैं, ऐसे में वक्फ की तरफ से इसका फायदा उठाने का आरोप लगाया जाता है.

2013 में वक्फ में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान फिर से संशोधन किया गया. वक्त के अधिकारों पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वक्फ ने आपकी किसी प्रोपर्टी को अपनी बताई तो ये आपको साबित करना होगा कि वो वक्फ की नहीं बल्कि आपकी है. इस फैसले के खिलाफ आपको किसी कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी. अगर ये फैसला आपके पक्ष में नहीं आया उस परिस्थिति में भी आप कोर्ट का रुख नहीं कर सकते बल्कि ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं. ट्राइब्यूनल का फैसला भी अगर आपके हक में नहीं रहा तो उसके खिलाफ आप न किसी हाईकोर्ट जा सकते हैं और न सुप्रीम कोट. ऐसा अनुमान है कि देश में इस वक्त जो 30 वक्फ बोर्ड है, उससे सालाना करीब 200 करोड़ का राजस्व हासिल होता है.

समर्थन में दलील

वक्फ बोर्ड के संशोधन में जो दलील जेडीयू की तरफ से दी गयी, उसमें कहा गया है कि मुसलमानों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून लाया जा रहा है. अगर कोई संस्था निरंकुश हो जाए तो पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को कानून लाने का हक है. उन्होंने सवाल किया कि इस देश में हजारों पंजाब सिखों को मारने का काम किसने किया? हजारों सिख समुदाय, जो टैक्सी ड्राइवर था, उसने कौन से किसकी हत्या की थी? इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए. विपक्ष बिल पर भ्रम फैला रहा है.

दूसरी तरफ, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ पर बिल से संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ बल्कि वक्फ एक्ट में पहले भी बदलाव हो चुका है. उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, ये बिल धार्मिक आजादी के खिलाफ नहीं है. वक्फ बिल किसी के अधिकारों पर चोट करने के लिए नहीं लाया गया बल्कि ये न्याय के लिए लाया गया.

उन्होंने कहा कि जिन्हें हक नहीं मिलता, उन्हें हक देने का बिल ला गया, कोई लॉ देश में सुपर लॉ नहीं हो सकता है. रिजिजू ने कहा कि किसी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं बल्कि जो कांग्रेस नहीं कर पायी वो हम कर रहे हैं और आज गलतियों को सुधारने का वक्त है. जाहिर तौर पर वक्फ में ये कोई पहला बदलाव नहीं है बल्कि इससे पहले भी बदलाव हुए हैं. ऐसे में धार्मिक मामलों की जब बात हो तो राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर सियासत न हो या ऐसी मंशा न हो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है. बहरहाल, नेक नीयत से कोई काम होता है तो हमेशा उसके नतीजे अच्छे होते हैं.

तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी दुनिया!

दो विश्व युद्ध देख चुकी दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर नजर आ रही है। इजराइल-हमास, रूस-यूक्रेन सहित कई देश जंग का सामना कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर अटैक करने की रणनीति बनाई है और ब्रिटेन में नई सरकार को हिंसा का अलग दौर देखना पड़ रहा है। बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। कई माह की लंबी लड़ाई के बाद भी रूस-यूक्रेन एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजरायल और हमास में विवाद चरस पर जा पहुंचा है। हालात इतने खराब हैं कि 10 देश इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं और इसका असर दूसरे कई देशों पर पड़ रहा है । इसी कारण सप्लाई चेन टूट चुकी है और महंगाई चरम पर चल रही है। जानते हैं जंग झेल रहे देशों के हालात...

यूक्रेन-रूस वॉर- पक रही नई खिचड़ी

दो साल से ज्यादा समय से चल रही यूक्रेन-रूस वॉर से अब इन देशों के सैनिक भी उकता चुके हैं। यूक्रेन को सबक सिखाने की बात करने वाले पुतिन अब नई खिचड़ी पका रहे हैं । हालात ऐसे हैं कि इतने महीनों के बाद भी कोई देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को एक तरफ अमेरिका से इ-16 फाइटर जैट मिल चुके हैं, दूसरी तरफ कई इलाकों में रूस ने अपनी पकड़ को मजबूत किया है। पश्चिमी यूक्रेन में सबसे ज्यादा रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं । यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि उन्हें अमेरिका के फाइटर जेट मिल गए हैं, लेकिन वे NATO देशों से और ज्यादा मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। वर्तमान में कीव में भी रूस ने कई ड्रोन अटैक किए हैं।

इजरायल-हमास के हालात

पिछले सालशुरू इजरायल-हमास तनाव अब और उग्र हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस जंग को शुरू किया और इजरायल के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया व कईयों को बंदी बना लिया। हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया और हमास को समाप्त करने की कसम खाई । दोनों देशों में 10 महीने से जारी युद्ध न थमा है औरन ही तनाव कम होता दिख रहा है। इस युद्ध में 40 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। गाजा में इजरायल के सबसे बड़े हमले होते दिख रहे हैं, वहां पर बच्चों से लेकर महिलाओं तक, बुजुर्गों से लेकर अस्पताल में पड़े मरीज तक, सभी की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में ही 33 लोगों की गाजा में मौत हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है, सबसे बड़ा मिसाइल अटैक तो कुछ दिन पहले ही हुआ है।

लेबनान-इजरायल तनाव चरम पर

मध्य पूर्व में लेबनान तनाव का नया केंद्र बना हुआ है। हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत के बाद इजरायल के साथ लेबनान की नोकझोंक चरम पर पहुंच चुकी है। असल में इजरायल पर ही आरोप है कि उसने हिजबुल्ला के प्रमुख को मौत के घाट उतारा है। यह हमला भी इसलिए हुआ है क्योंकि हिजबुल्ला ने अपने एक अटैक में इजरायल के कुछ बच्चों को मार गिराया था। उसके बाद से ही बदले की भावना से जल रहा इजरायल हिजबुल्ला को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। इसी वजह से भारत,ऑस्ट्रेलिया और अब अमेरिका जैसे देश अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान से निकलने के लिए कह रहे हैं।

इजरायल-ईरान में बढ़ी टेंशन

लेबनान में हिजबुल्ला प्रमुख और ईरान में हमास के चीफ की मौत ने नई जंग के हालात पैदा कर दिए हैं।दोनों इन हमलों के लिए भी इजरायल को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। इसी वजह से अब ईरान भी इजरायल से बदला चाहता है। उसकी तरफ से कई मिसाइल हमले भी हाल ही में इजरायल पर हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि तनाव इतना ज्यादा है कि आने वाले दिनों में युद्ध का नया मोर्चा दोनों देशों के बीच में खुल सकता है। इजरायल भी झुकने के मूड में नहीं दिख रहा है, उसकी तरफ से भी एलान हुआ है कि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

बांग्लादेश गृह युद्ध की ओर

भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय गृह युद्ध की ओर बढ़ता दिख रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पूरे देश में ही कर्फ्यू लगाना पड़ा है। इंटरनेट बंद चल रहा है और कई लोगों की मौत हो चुकी है। असल में बांग्लादेश में 1971 में पाकिस्तान से देश की आजादी के लिए लड़ने वाले युद्ध नायकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने की बात है। अब ढाका और दूसरे शहरों के छात्र इसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो इसे भेदभाव वाला मानते हैं, इसे 10 फीसदी तक करने की बात करते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी यह है कि बांग्लादेश में युवा सराकरी नौकरी को लेकर काफी जज्बाती रहते हैं, यह उनके लिए किसी बड़े पद से कम नहीं होता है। ऐसे में अगर उनके अवसर ही कम हो जाएंगे तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लग जाएगी। इसी वजह से सड़कों पर इस तरह से हिंसा उबाल मार रही है।

दंगों के बुरे दौर से जूझ रहा ब्रिटेन

उत्तर पश्चिमी इंग्लैंज में चाकू से किए गए हमले में तीन बच्चियों की मौत के बाद से ही ब्रिटेन में हालात बेकाबू हो चुके हैं, कई सालों बाद वो सबसे खराब दंगों से जूझ रहा है। ब्रिटेन की सड़कों में हिंसक भीड़ और जलती हुई दुकानों की तस्वीरें अब पूरी दुनिया में शेयर की जा रही है। इस पूरे बवाल का कारण आरोपी से जुड़ी एक खबर है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि साउथपोर्ट का हमलावर एक अप्रवासी मुस्लिम था जो अवैध रूप से ब्रिटेन में आया था। इसके बाद अप्रवासियों के खिलाफ विरोध की लहर देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की हिंसा के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

साप्ताहिक समय माया

भारत में स्वतंत्रता दिवस का महत्व और प्रतीक

भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था लेकिन जब देश को 15 अगस्त, 1947 को आजादी मिली तो वे इसके जश्न में शामिल नहीं हुए।

भारत की आजादी से जुड़ी दस दिलचस्प बातें

» महात्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे।

» जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आजाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा था, "15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं। इसमें शामिल हो अपना आशीर्वाद दें।"

» गांधी ने इस खत का जवाब भिजवाया, "जब कलकत्ते में हिंदू-मुस्लिम एक दूसरे की जानले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूं। मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा।"

» जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण 'ट्रिस्ट विद डेस्टनी' 14 अगस्त की मध्यरात्रि को वायसरायलॉज (मौजूदा राष्ट्रपति भवन) से दिया था। तब नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना,लेकिन गांधी उस दिन नौ बजे सोने चले गए थे।

» 15 अगस्त, 1947 फोलॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेज गार्डेन में एक सभा को संबोधित किया।

» हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं। लेकिन 15 अगस्त, 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त, 1947 को लालकिले से झंडा फहराया था।

» भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सचिव कैंपबेल जॉनसन के मुताबिक मित्र देश की सेना के सामने जापान के समर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही थी, इसी दिन भारत को आजाद करने का फैसला हुआ।

» 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेडक्लिफलाइन की घोषणा से हुआ।

» भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया,लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्र गान नहीं था. रवींद्रनाथ टैगोर जन-गण-मन 1911 में ही लिख चुके थे,लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया।15 अगस्त भारत के अलावा तीन अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त, 1945 को आजाद हुआ ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त, 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त,1960 को आजाद हुआ।

15 अगस्त के अनछुए पहलू

तुम मम्मी-पापा से किसी चीज की जिद करते से और बार-बार मांगने के बाद जब वह तुम्हें मिलती है तो कितनी खुशी होती है ना। समझ ही नहीं आता कि नाचें, गाएं या क्या करें उसे सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ ऐसा ही हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब करीब 300 साल के बाद हमारे देश को आजादी मिली थी। उस समय के अनछुए पहलू जानते हैं।

मना उत्सव - 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी का उत्सव मना रहा था। देश के लगभग हर हिस्से में लोग इतने उत्साहित थे कि सड़कों पर नाच रहे थे। राष्ट्रपति भवन, संसद आदि के आसपास करोड़ों लोगों का हुजूम था। पूरे दिन यही हाल रहा।

कहां थे गांधी जी - महात्मा गांधी उस पूरे दिन किसी सेलीब्रेशन में शामिल नहीं हुए। वे पश्चिम बंगाल के बेलियाघाट के एक घर में थे। सबसे पहले गांधी जी ने ब्रिटेन में रहने वाले अपने दोस्त अगाथा हेरीसन को एक पत्र लिखा और उन्हें बताया कि वे ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि देश को आजादी मिली। उन्होंने उस दिन उपवास रखा था। पूरे दिन में वे कई छात्रों से मिले और कुछ लिखते रहे।

पहले ही हो गया था फैसला- भारत को आजाद करने का फैसला ब्रिटेन की सरकार ने 26 फरवरी 1947 को ही कर लिया था। इस दिन ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पॉलिसी की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि ब्रिटेन की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा।

पहली मीटिंग

14 अगस्त को आजादी की घोषणा होते ही इंडिपेंडेंस मीटिंग बुलाई गई। यह मीटिंग नई दिल्ली में रात 11 बजे बुलाई गई। इस सेशन की अगुवाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इस मौके पर ओपनिंग सॉन्ग यानि मीटिंग आरंभ करने से पहले वंदे मातरम सुचेता कृपलानी ने गाया था।15 अगस्त के दिन की शुरुआत सुबह 8.30 बजे हुई, जब वायसरीगल लॉज (जिसे अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है) में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई सरकार ने सेंट्रल हॉल (आज जिसे दरबार हॉल कहा जाता है) में शपथ ली।

एक साल पहले मिली आजादी

लॉर्ड माउंटबेटन से कहा गया था कि वे जून 1948 तक भारत को सभी अधिकार ट्रांसफर करने की व्यवस्था कर लें। इसके बाद लॉर्ड ने भारतीय नेताओं से बात की, पर यह उतना आसान नहीं था, क्योंकि जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर कई विवाद थे। लॉर्ड के लिए समस्या बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए उन्होंने 1947 में ही आजादी को लेकर सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी कर दी थी।

आजादी के लिए आधी रात क्यों - जब 3 जून को यह फैसला किया गया कि 15 अगस्त को आजादी दी जाएगी तो भारतीय ज्योतिषियों ने इस पर ऐतराज किया। उनके अनुसार यह दिन काफी अमंगल होता देश के लिए। लेकिन लॉर्ड तो इसी दिन के लिए अड़े हुए थे, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा कि आजादी का समय 14 अगस्त रात 12 बजे हो, क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार अगले दिन सूर्योदय से दिन आरंभ माना जाता है, इसलिए 15 अगस्त के अशुभ दिन से बचा जा सकेगा और अंग्रेज यह मानते हैं कि रात 12 बजे से दिन बदल जाता है, इसलिए लॉर्ड की बात का मान भी रखा जा सकेगा।

और किसे मिली आजादी - ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही इसी दिन आजादी मिली। भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, बहरीन और रिपब्लिक ऑफ कांगो को भी 15 अगस्त की तारीख को ही आजादी मिली। दक्षिण कोरिया को वर्ष 1945 में, बहरीन को 1971 में और रिपब्लिक ऑफ कांगो को 1960 में आजादी मिली।

नेहरू जी की स्पीच - आजादी की पूर्व संध्या पर जब जवाहर लाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टनी नामक स्पीच दी, तब वे भारत के आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री पद की शपथ तो उन्होंने 15 अगस्त को ली थी।

आजादी आंदोलन के 10 महानायक जिन्होंने दिलाई देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति

1. अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर करने वालों में महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करके भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिशर्स की ओर से नमक पर टैक्स लगाए जाने के विरोध में गांधी जी की ओर से शुरू किया गया दांडी मार्च बहुत सफल हुआ था। इसके अलावा उन्होंने समाज की कुरीतियों को खत्म करने की भी कोशिश की थी।

2. भारत की आजादी में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने राज्य झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए जंग छेड़ी थी। साल 1858 में हुए दो हफ्तों के इस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि बाद में अंग्रेजों से लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुईं।

3. अपने जज्बे और जोश से अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने में क्रांतिकारी भगत सिंह ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने चाचा के साथ आजादी की लड़ाई में कदम रखा था। बाद में उन्होंने धरती मां को गुलामी से मुक्त कराने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया था। उन्होंने सन् 1921 में असहयोग आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी।

4. स्वतंत्रता सेनानियों में एक महत्वपूर्ण नाम मंगल पांडे का भी है। वे ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ साल 1857 में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंनो ब्रिटिशर्स की ओर से बनाए जाने वाले कारतूसों को बदले जाने की मांग की थी। क्योंकि इसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था और इसे खींचने के लिए मुंह लगाना पड़ता था। इससे हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा था।

5. आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बड़ा हाथ था। उन्होंने भारतीय कांग्रेस ज्वाइन करके अवज्ञा आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई थी। नेताजी ने जर्मनी में जाकर इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था।

6. स्वतंत्रता सेनानियों में लाला लाजपत राय का भी नाम शान से लिया जाता है। उन्होंने जलियावाला हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। इस संघर्ष में हुए लाठीचार्ज के दौरान वे बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

7. स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले आंदोलनकारी बालगंगाधर तिलक ने भी आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पूरे भारत में घूम-घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति तैयार की थी।

8. क्रांतिकारी अशफाकउल्ला खान को उनके तेज तर्रार अंदाज के लिए जाना जाता है। वे उग्र विचार धारा के थे। उन्होंने कांकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना लूटा था।

9. सन् 1857 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले बहादुर शाह जफर का नाम भी शान से याद किया जाता है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से लोहा लेने के लिए विशाल मोर्चा तैयार किया था।

10.क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु का नाम भी आजादी की लड़ाई में शान से लिया जाता है। वे भगत सिंह के साथी थे। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए वे नौजवानों को जोड़ने और रणनीति बनाने का काम करते थे।

आजादी के लिए त्याग और बलिदान देने वाली

वीरांगनाएं, जिन्हें हम भूल गए..!

देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए न जाने कितने फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर हमने यह आजादी पाई थी। देश ऋणी है उन क्रांतिवीरों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। परंतु दुःख है इतिहास में कुछ खास लोगों को ही जगह मिली। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आजादी के लिए किए गए लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्र भारत में भी वह सम्मान और पहचान न पा सके जिसके वे हकदार थे। इन वीर सेनानियों में अनेक महिलाएं भी थीं जिन्होंने न केवल क्रांतिकारियों की तरह तरह से सहायता की बल्कि संगठनों व सभाओं का नेतृत्व भी किया। आइए जानें कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गईं।

■ **झलकारी बाई :** झलकारी बाई का जन्म 22 नंवबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। पिता ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए उन्हें बड़े प्यार से पाला और घुड़सवारी व तीरंदाजी की शिक्षा दी। उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक के साथ हुआ। यहां वे रानी के संपर्क में आईं। रानी ने उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें अपने महिला सैनिकों की शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया। यहां उन्होंने तोप व बंदूक चलाना सीखा और दुर्गा दल की सेनापति बनीं। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थीं। शत्रु को धोखा देने के लिए कई बार वे रानी के वेश में भी युद्धाभ्यास करती थीं। अपने अंतिम समय में वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं और रानी को किले से भागने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोकगाथाओं और लोककथाओं में अमर है।

■ **रानी चेनम्मा :** चेनम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थीं। उनका जन्म 1778 में बेलगाम जिले के ककती गांव में हुआ था। पहले पति फिर पुत्र की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अपनी 'राज्य हड़प नीति' के तहत कित्तूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। रानी को यह मंजूर नहीं था, उन्होंने अंग्रेजी सेना से जमकर लोहा लिया। अपूर्व शौर्य प्रदर्शन के बाद भी वे अंग्रेजी सेना का मुकाबला न कर सकीं। उन्हें कैद कर लिया गया। 21 फरवरी 1829 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने तमाम रजवाड़ों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया।

■ **कनकलता बरुआ :** इनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को असम के सोनीपुर जिले के गोहपुर गांव में हुआ था। अल्पायु में ही माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी नानी ने उन्हें पाला-पोसा। 1931 में गमेरी गांव में रैयत अधिवेशन हुआ जिसमें तमाम क्रांतिकारियों ने भाग लिया। सात साल की कनकलता भी अपने मामा के साथ अधिवेशन में गईं। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों पर राष्ट्रदोह का मुकदमा चला तो पूरे असम में क्रांति की आग फैल गई। कनकलता क्रांतिकारियों के बीच धीर-धीरे बड़ी होने लगीं। एक गुप्त सभा में 20 सितम्बर 1942 को तेजपुर कचहरी पर तिरंगा फहराने का निर्णय हुआ। उस दिन बाइस साल की कनकलता तिरंगा हाथ में थामे जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं। अंग्रेजी सेना की चेतावनी के बाद भी वे रुकी नहीं और छाती पर गोली खाकर शहीद हो गईं। अपनी वीरता व निडरता के कारण वे वीरबाला के नाम से जानी गईं। आज सबसे कम उम्र की बलिदानी कनकलता का नाम भी इतिहास के पन्नों से गायब है।

■ **दुर्गावती बोहरा (दुर्गा भाभी) :** दुर्गावती का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को कौशाम्बी जिले के शहजादपुर गांव में हुआ था। दस वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ। भगवती चरण के पिता शिवचरण रेलवे में उच्च पद पर आसीन थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब की पदवी दी थी। पिता के प्रभाव से दूर भगवती चरण का क्रांतिकारियों से मिलना-जुलना था। उनका संकल्प देश को अंग्रेजी दासता से मुक्त कराना था। 1920 में पिता की मृत्यु के बाद पति-पत्नी दोनों खुलकर क्रांतिकारियों का साथ देने लगे। 28 मई 1930 को रावी नदी के तट पर साथियों के साथ बम बनाने के बाद परीक्षण करते समय बोहरा शहीद हो गए। अब दुर्गावती जो साथियों में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती थीं और अधिक सक्रिय हो गईं। 9 अक्टूबर 1930 को दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली पर गोली चलाई परंतु वह बच गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने ही गोली मारी थी, जिससे पुलिस उनके पीछे पड़ गई और गिरफ्तार कर लिया। दुर्गा भाभी का काम क्रांतिकारियों को हथियार पहुंचाना था। वे भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त आदि के साथ काम करती थीं। उनकी शहादत के बाद वे अकेली पड़ गईं और अपने पांच साल के बेटे शचींद्र को शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली और फिर लाहौर चली गईं। जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तीन वर्षों तक नजरबंद रखा। 1935 में वे गाजियाबाद आ गईं और एक विद्यालय में पढ़ाने लगीं। इसके बाद अन्य कई स्कूलों में भी उन्होंने अध्यापन किया और 14 अक्टूबर 1999 को इस दुनिया से विदा हो गईं। इस क्रांतिकारी महिला को स्वतंत्र भारत में कोई सम्मान व पहचान नहीं मिली।

■ **मातंगिनी हजारा :** मातंगिनी हजारा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांवमें हुआ था। गरीबी के कारण बारह वर्ष की उम्र में उनका विवाह 62 वर्षीय विधुर के साथ कर दिया गया। छः वर्ष के बादवे निःसंतान विधवा हो गईं। जैसे-तैसे गरीबी में दिन गुजार रही थीं। 1932 में देशभर में स्वाधीनता आंदोलन चला और जुलूस उनके घर के सामने से गुजरा तो वे भी जुलूस के साथ चल पड़ीं। इसके बाद वे तन-मन-धन से देश के लिए समर्पित हो गईं। 17 जनवरी 1933 को कर बंदी आंदोलन का नेतृत्व किया, गवर्नर एंडरसन को काले झंडे दिखाए तो गिरफ्तार कर ली गईं। छः मास का सश्रम कारावास हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की रैली के लिए घर-घर जाकर 5000 लोगों को तैयार किया। तिरंगा हाथ में लिए रैली का नेतृत्व करते हुए मातंगिनी जुलूस के साथ जब सरकारी डाक बंगले पर पहुंचीं तो पुलिस ने वापस जाने को कहा। मातंगिनी टस से मस न हुईं। अंग्रेजी सिपाहियों ने गोली चला दी। गोली मातंगिनी के बाएं हाथ में लगी। तिरंगे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। दूसरी गोली दाएं हाथ में और तीसरी माथे पर लगी। मातंगिनी वहीं शहीद हो गईं। इस बलिदान ने क्षेत्र के लोगों में जोश भर दिया परिणामस्वरूप लोगों ने दस दिनों के अंदर ही अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया और स्वाधीन सरकार स्थापित की, जिसने 21 माह काम किया। आज हममें से कितने लोग हैं जो मातंगिनी हजारा जैसी कोई वीरांगना हुई थी यह जानते हैं?

■ **बीनादास :** बीनादास का जन्म 24 अगस्त 1911 को बंगाल प्रांत के कृष्णानगर गांव में हुआ था। वे कोलकाता में महिलाओं द्वारा संचालित अर्धक्रांतिकारी संगठन छात्रा संघ की सदस्या थीं। 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। 1932 में उन्हें एक दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को मारने की जिम्मेदारी दी गई। इस समारोह में उन्हें भी डिग्री मिलनी थी। स्टेनली जब भाषण देने लगा, वे अपनी सीट से उठीं और गवर्नर के सामने जाकर गोली चला दी। उनका निशाना चूक गया, स्टेनली बच गया, परंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीनादास को दस साल कैद की सजा सुनाई गई, साथियों के नाम बताने के लिए जेल में तरह तरह की यातनाएं दी गईं, परंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला। 1947 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्य रहीं। 1986 में ऋषिकेश में उनकी लाश मिली।

भारत भूमि ऐसे बलिदानों और बलिदानियों से भरी पड़ी है। हमें बेशक स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य नहीं मिला परंतु आज हम उन अमर शहीदों व उनके परिवार वालों को ढूंढकर उचित सम्मान तो दे ही सकते हैं।

**आओ झुककर सलाम करें उनको,
जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है,
खुशनसीब होता है वह खून
जो देश के काम आता है।**

साप्ताहिक समय माया

देश की कृषि को खाद बीज बिजली की कीमत बढ़ा किया बर्बाद

पेज 1 का शेष

सिर्फ मोदी ही हैं जो यह कर सकते हैं ; वे वैज्ञानिकों को विज्ञान पढ़ा सकते हैं, बिल गेट्स को कंप्यूटर कनेक्टिविटी पढ़ा सकते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र के टॉपर्स को पढ़ने की टिप्स दे सकते हैं, खिलाड़ियों को खेल सिखा सकते हैं तो कृषि अर्थशास्त्रियों को ज्ञान देना तो उनके बांये हाथ का खेल है। हालांकि इतना सब बोलने की भी उन्हें जरूरत नहीं थी; सिर्फ अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही खड़ा कर देते तो कृषि के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां शब्दशः मूर्त रूप में साकार हो जातीं।

दुनिया बिन कहे ही समझ जाती कि जो सरकार फसल के दाम मांगने के संगीन जुर्म में 6 किसानों की दिनदहाड़े हत्या करवाने वाले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री को देश का कृषिमंत्री बना सकती है, उसका किसान, खेती और किसानी के प्रति प्रेम कितना प्रबल है। न होता, तो राज्यसभा में दिया गया उनका वह दम्भी कबूलनामा ही दिखा देते।

जिसमें वे ज़रा सी भी लज्जा या पश्चाताप के बिना एकदम शोहदों की तरह उन 6 युवा किसानों की पुलिस द्वारा की गयी हत्याओं को इस आधार पर जायज ठहरा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी किसानों पर गोलियां चलवाई जाती रही हैं। बहरहाल, फिलहाल उनके द्वारा किये गए दावों की सच्चाई पर ही एक नजर डाल लेते हैं।

अपने भाषण में वे भारत की खेती और किसानी और उसके 2000 साल पुराने ग्रंथ 'कृषि पाराशर' का जिक्र करते हुए दावा कर रहे थे। मगर उनके दावे ही इस बात की चुगली खा रहे थे कि जिसे वे कथित 2000 साल पुराना ग्रन्थ बता रहे थे, उस 'कृषि पाराशर' की किताब में मोदी और उनकी सरकार ने झांका तक नहीं है।

यदि उसका पहला पन्ना ही पलट लिया होता तो उन्हें पता होता कि दो हजार साल नहीं बल्कि आठवीं सदी के बाद महर्षि पराशर द्वारा लिखे गए, कृषि के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताने वाले इस ग्रन्थ की शुरुआत में ही कहा गया है कि 'अन्न ही प्राण है, अन्न ही बल है; अन्न ही समस्त अर्थ का साधन है।

देवता, असुर, मनुष्य सभी अन्न से जीवित हैं तथा अन्न धान्य से उत्पन्न होता है और धान्य बिना कृषि के नहीं होता। कृषि बिना कृषक के नहीं होती।' और उस किसान की दशा क्या है? यह जिस वक़्त मोदी ऊंची-ऊंची हांक रहे थे उसी वक़्त महाराष्ट्र का सिर्फ एक जिला अमरावती बता रहा था। यहां मात्र 6 महीने में 557 किसान आत्महत्या करके किसानों की दुश्वारी के आत्मघाती होने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रहे थे। यही नहीं पूरे विदर्भ में आत्महत्याओं की झड़ी सी लगी हुयी थी।

समस्या सिर्फ विदर्भ की ही नहीं थी, कर्नाटक भी महज 15 महीनों में 1182 किसान आत्महत्याओं के साथ नया रिकॉर्ड बना रहा था। बाकी देश में भी कहीं कम कहीं ज्यादा इसी तरह की मौतों की खबरें आयीं और कारपोरेट मीडिया द्वारा दबाई जा रही थीं।

खुद सरकार अपने बजट के पहले दिए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में कबूल कर रही थी कि देश में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर लगातार गिरती जा रही है, और गिरते-गिरते 2022-23 की लगभग 5 प्रतिशत से गिरकर एक चौथाई रह गयी है और 1.4 तक आ गयी है। अगर यही खेती और किसान के लिए बेहतरी है तो जाहिर है कि बदतरी के लिए कोई नया शब्द ढूंढना होगा।

दुनिया के 75 देशों से आये कोई 1000 कृषि अर्थशास्त्रियों का मोदी जिन 'भारत के 12 करोड़ किसानों, 3 करोड़ से अधिक महिला किसानों, 3 करोड़ मछुआरों और 8 करोड़ पशुपालकों की ओर से सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत' करते हुए हांक रहे थे कि यहां 50 करोड़ पशुधन हैं। मैं आपका कृषि और पशु-प्रेमी देश भारत में स्वागत करता हूं।'

उन्हीं मोदी और उनकी पार्टी की सरकारों में पशुपालकों और उसके लिए पशु खरीद कर लाने वालों की किस तरह से निर्मम हत्याएं की जा रही थीं, यह तकरीबन हर सप्ताह की खबर बन रही थी। उसी देश में जब मोदी की किसान विरोधी नीतियों को वापस लौटाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे 750 किसान शहादतें दे रहे थे, तब मोदी बांसुरी बजा रहे थे।

मोदी ने कहा कि आज 'भारत खाद्य अधिशेष वाला देश है, दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, और खाद्यान्न, फल, सब्जियां, कपास, चीनी, चाय और मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।' उन्होंने उस समय को याद किया जब भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए चिंता का विषय थी, जबकि आज भारत वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए समाधान प्रदान कर रहा है।'

वे जिस भंडारों में भरे, अनबिके अनाज के अधिशेष के लिए अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे थे, यह दरअसल वह अनाज है जो भूखे भारतीयों के पेट में पहुंचना था, मगर महंगी कीमतों में उसे खरीदने की ताकत न होने के चलते गोदामों में ही सड़ता रहा और दुनिया के दूसरे देशों में शराब और ईंधन बनाने के लिए भेजा जाता रहा।

नतीजा यह निकला कि जब वे पूरी दुनिया का पेट भरने और उसका सही तरीके से पोषण करने का दावा ठोक रहे थे, तब खुद उनका देश भारत भुखमरी की त्रासदी के आंकड़ों में 125 देशों में से 111 वें स्थान पर अपनी कातर स्थिति दर्ज करा रहा था। उनकी सरकार इन आंकड़ों का खंडन कर रही थी। मगर दूसरी तरफ देश के 80-85 करोड़ नागरिकों को 5 किलो अनाज हर महीने देकर उन्हें ज़िंदा रखने को अपनी उपलब्धि बताकर, इस भयानक सच्चाई को कबूल भी कर रही थी।

उनका दावा था कि 'उनकी आर्थिक नीतियों के केंद्र में कृषि है' वह कितनी है, इसे महज कुछ दिन पहले संसद में पेश किया गया उनकी सरकार का बजट बता रहा था। जिसमें कृषि और उससे जुड़े कामों के बजट में मात्र पिछले साल की तुलना में 21. 2 प्रतिशत की कमी कर दी गयी थी।

गरीब किसानों की मदद करने वाले ग्रामीण रोजगार गारंटी क़ानून को मखौल बनाकर रख दिया गया था। उनकी आर्थिक नीतियों के केंद्र में कृषि किस तरह से है, इसका प्रमाण वे तीन कृषि क़ानून थे, जिन्हें किसानों ने पानी 378 दिन की लड़ाई के बाद वापस कराया था। और जिन्हें पिछले दरवाजे से वापस लाने की तिकड़में आज भी जारी हैं।

जिन 'छोटे किसानों को मुख्य ताकत और खाद्य सुरक्षा का आधार' बताते हुए उनके लिए पिछली 10 वर्षों में 1900 नई जलवायु अनुकूल किस्में सौंपने की डींग वे हांक रहे थे, उसकी असलियत जहां वे भाषण दे रहे थे उससे ज़रा सी दूरी पर, राजधानी का ही विस्तार माने जाने वाले हरियाणा में किसान अपनी कपास की बर्बाद फसल को आग लगाकर, उस पर ट्रैक्टर चलाकर बयान कर रहा था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के झूठे दावों वाले बीटी कॉटन के बीज से उपजी तबाही के दंश झेल रहा था।

इन छोटे किसानों के लिए वाहवाही लूटने वाले मोदी, यह सच जानबूझकर छुपा गए कि इनमें से ढाई से तीन हजार किसान हर रोज अपनी खेती छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब वह उनके लिए गले का फंदा बन चुकी है। यह भी कि अब इनका बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, ऐसा है जो बजाय बड़े किसान की जमीन बटाईदारी पर लेने के औने-पौने दामों में अपनी जमीन उसे दे रहा है।

उनकी आर्थिक नीतियों के केंद्र में यकीनन कृषि है, लेकिन विकास के लिए नहीं विनाश के लिए। यह वह आर्थिक नीतियां हैं, जिन पर चलते हुए हर वर्ष लाखों एकड़ खेती की जमीन को दरबारी कारपोरेटियों को सौंप कर किसान को बेदखल और कृषि को तबाह किया जा रहा है। ऐसे हालात पैदा किये जा रहे हैं, जिनका असर आने वाली कई पीढ़ियों को भीषण गरीबी की बाढ़, रोजगारहीनता के सूखे, यहां तक कि अठारहवीं सदी के भयानक अकालों के रूप में भी भुगतना पड़ सकता है।

बहरहाल, भले काले चावल के बहाने सही उनकी जुबान पर मणिपुर का नाम तो आया। लगता है उन्हें सिर्फ 'सुपर फूड्स' के नाम पर मार्केटिंग कर रही कारोबारी कंपनियां के विज्ञापन ही दिखते हैं; अंडमान से कश्मीर, बिहार और बाकी ऐसे प्रदेश नहीं दिखते जहां किसानों द्वारा उपजाए गए चावल की कीमतें 1000 से 1200 रुपयों की शर्मनाक निचाइयां छू रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने 10 साल के राज में 10 लाख हेक्टेयर जमीन को उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई से सिंचित करने का काम किया है।

इसकी असलियत उनके ही विभागों की रिपोर्ट्स बता रही थी। केन्द्रीय जल आयोग कह रहा था कि देश के 150 बड़े जल स्रोत अपनी क्षमता से 27 प्रतिशत नीचे चले गए हैं। कारपोरेट कंपनियों के अंधाधुंध दोहन से भूजल स्तर पाताल की निचाई तक जा पहुंचा है, और आधा भारत बाढ़, एक तिहाई भारत सूखे की चपेट में है।

कर्नाटक में चार दशक का सबसे भयानक सूखा है। बिगड़ते मौसम के चलते तमिलनाडु के किसान नारियल के पेड़ काटने के लिए मजबूर हैं और इसी जनवरी और मार्च के बीच मौसम के उतार-चढ़ाव के चलते चाय के उत्पादन में 2 करोड़ 10 लाख किलोग्राम से अधिक की कमी आयी है।

देश के 9 प्रदेशों में 20 से 49 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है। वहीं 6 राज्य अतिवृष्टि के शिकार बने हैं। ऐसे में चारों तरफ हरा हरा अगर किसी को दिख रहा है तो वे मोदी ही हैं। बाकी देश तो उन्हें चुने का दंड भुगतने का अभिशाप अपनी खेती के दिनों दिन अलाभकारी होने के रूप में झेल रहा है।

वे जिन-जिन नयी तकनीकों और प्रयोगों को गिना रहे थे, वे 'ज्यों-ज्यों दिन की बात की गयी, त्यों-त्यों रात हुई' जैसे थे। जैसे उन्होंने ड्रोन से फसलों के डिजिटल सर्वे को किसानों के लिए किया गया भारी काम बताया जबकि असल में इसके द्वारा जुटाए गए कथित आंकड़ों में बीमा कम्पनियां अपने हिसाब से तोड़मरोड़ कर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे से बचने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।

किसान की भूमि का रिकॉर्ड तक गड़बड़ा रहा है। उन्होंने 1 करोड़ किसानों को उस तथाकथित नेचुरल फार्मिंग, बिना खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल के किये जाने वाली खेती से जोड़ने का दावा किया, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह वही खेती है जिसका खामियाजा अभी हाल ही में श्रीलंका के किसानों ने दिवालिया होकर और वहां की जनता ने भुखमरी का शिकार होकर चुकाया है।

इधर वे प्रधानमंत्री शब्द के पुछल्ले वाली किसान हितैषी योजनाओं के नाम दर नाम गिना रहे थे, 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना और न जाने कौन-कौन सी योजनाओं का हितग्राही होने का दावा कर रहे थे, उधर उनकी वित्त मंत्राणी इन सबके लिए बजट आवंटन को या तो स्थिर बनाये रखने या पहले से घटाने के प्रस्ताव रख रहीं थीं।

बहरहाल कुछ सच इतने विराट और चमकीले हरफों में समय की दीवार पर दर्ज होते हैं कि उन्हें झूठ की सुनामी भी ओझल या धुंधला नहीं कर सकती। भले मोदी ने जिक्र नहीं किया मगर दुनिया भर से आये अर्थशास्त्रियों को पता था कि जहां खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री उन्हें भारत की कृषि और किसानों की चमचमाती छवि दिखा रहे हैं, उससे आवाज भर की दूरी पर दिल्ली की छहों बॉर्डर्स पर अभी-अभी देश के किसान कोई 13 महीनों तक डेरा डाले हुए थे।

खेती किसानी पर कारपोरेट कंपनियों के कब्जे को रोकने और फसल के उचित दाम देने सहित अपनी मांगों को उठा रहे थे, अपने संघर्ष की धमक से देश दुनिया को हिला रहे थे। यही ऐतिहासिक संग्राम था, जिसने मोदी की पार्टी को संसद में अल्पमत में ला दिया और सरकार बनाने का नैतिक अधिकार छीन लिया।

किसान आन्दोलन के केंद्र की 38 सीटों पर ही नहीं देश की ग्रामीण आबादी के बहुमत वाली 159 लोकसभा सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के उलटे बांस बरेली को बांध दिए। यहां तक कि उनके कृषि मंत्री तक को चुनाव हरा दिया।

इस सबके बाद भी यदि वे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर अडानी-अम्बानी की बढ़ती तोंदों को अपनी कामयाबियों के रूप में गिनाते हुए आत्ममुग्ध होना चाहते हैं तो भले हो लें, उनका पालक-पोषक कारपोरेट मीडिया उनके झूठों का गुणगान कर सकता है मगर ये पब्लिक है और वो सच जानती है।

पड़ोसी बांग्लादेश की आग में मोदी की चुप्पी

पेज 1 का शेष

4. ब्रिटानिया, GCPL, डाबर, एशियन पेंट्स, पिडीलाइट, जुबिलेंट फूडवर्क्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर जैसी कंपनियां बांग्लादेश के बाज़ारों से बड़ी कमाई करती हैं..

5. यार्न/कपास का भारत बांग्लादेश को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है..भारत के कपास एक्सपोर्ट का लगभग 30% बांग्लादेश में है

6. गोकलदास एक्सपोर्ट, KPR मिल, अरविंद लिमिटेड, SP अपारेल, सेंचुरी एनका, किटेक्स गारमेंट्स, नाहर शिपिंग वग़ैरह भी बांग्लादेश से क़रीबी ताल्लुक रखते हैं..

7. भारत बांग्लादेश को सब्ज़ी, फल, कॉफ़ी, चाए, मसाले, चीनी, डीज़ल, पेट्रोल, केमिकल का बड़ा एक्सपोर्ट करता है..

8. भारत की ज्यादातर लोहा/सरिया कंपनियों का बड़ा बाज़ार बांग्लादेश है..हमारी सारी एयरलाइन्स बांग्लादेश में विमान सेवा देती हैं.. रोज़ की एक से ज्यादा फ्लाइट है..

9. भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश जाता है.. भारत की इंजीनियरिंग/सॉफ्टवेयर कंपनियों ने बांग्लादेश की इकॉनमी को संभाल रखा है..

10. सोचिए, इन सारे व्यापारों के लिए कितना बड़ा मैनपॉवर, ट्रांसपोर्ट, लेबर लगता है..और कितना बड़ा डायरेक्ट/इनडाइरेक्ट रोज़गार पैदा होता है..

11. इस के 'अलावा शिक्षा में बांग्लादेश भारत के छात्रों को आरक्षण देता है और भारत भी बांग्लादेश के छात्रों को आरक्षण देता है..कल्चर भी एक बड़ा हिस्सा है..

आज भारत चाहे तो पूरे बांग्लादेश को घुटने पर ला सकता है..किसी फ़ौज या हथियार की ज़रूरत नहीं है..1 महीने सप्लाई रोक दी जाए तो बांग्लादेश रेंगते हुए दिल्ली आ कर भीक मांगेगा..

फिर देखते हैं बांग्लादेश के 'आतंकी' जमा'त ए इस्लामी और बेगम ख़ालिदा ज़िया की औक़ात..सुब्ह से शाम तक 'हिंदू ख़तरे में है' बोल कर क्या होगा? कुछ करते क्यों नहीं? पर क्या पीएम नरेंद्र ऐसा करेंगे? क्योंकि बांग्लादेश में अदाणी के व्यापार के चक्कर में जो 'कबाड़-कचरा' फैला रखा है वो अगर बांग्लादेश बता देगा तो 'इज़्ज़त ख़त्म!!

दिमाग़ से बड़ा हथियार नहीं, ईमानदारी से बड़ी मिसाइल नहीं और देश के स्वार्थ से बड़ा कोई स्वार्थ नहीं..

पर पीएम नरेंद्र के लिए इन तीनों बातों का कोई मतलब नहीं..वरना पिद्दी से बांग्लादेश की क्या औक़ात की भारत को आंख दिखाए? ऐसी कौन सी कमज़ोर नस है कि इश नरेंद्र ख़ामोश हैं?

सारडा, भदोरिया, भेषज दशोंधी 50:30:20

पेज 8 का शेष

क्षेत्रीय डिस्पेंसरियों के डॉक्टर से लेकर इंदौर मुख्यालय व दिल्ली के मुख्यालय तक सबका कमीशन जुड़ा होता है। भोपाल में गायत्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अरेरा ट्रामा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, कैरियर इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज, नवोदय कैंसर हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिल्वर लाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनंत हार्ट हॉस्पिटल, नर्मदा ट्रॉमा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एलएन मेडिकल कॉलेज एंड जेके हॉस्पिटल, चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, चिरायु हेल्थ एंड मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स हॉस्पिटल सब भोपाल के वे निजी चिकित्सालय हैं जहां श्रमिकों की गंभीर चिकित्सा के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए का भुगतान में मोटा कमीशन खाया जाता है। इंदौर में वी1 हॉस्पिटल, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री वैष्णव शैक्षणिक एवं परमार्थिक न्यास, ज्योति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, मेडिप्लस हॉस्पिटल, मॉडर्न डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर, श्री इम्यूनो डायग्नोस्टिक अरिहंत गुमास्ता नगर, श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, ओ रेटिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकेयर हॉस्पिटल, चरक हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, गोकुलदास हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर में बॉम्बे हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, अनंत नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल और नेशनल हॉस्पिटल, त्रिवेणी हेल्थकेयर, जामदार हॉस्पिटल, ग्वालियर में केडीजे और केएम हॉस्पिटल बीआइएमआर सूर्य मंदिर रोड रेजिडेंसी मुरार, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल देवास में अमलतास इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज आदि ये 38 निजी चिकित्सालय मोटे कमीशन पर जबरदस्ती डिस्पेंसरियों के डॉक्टरों से केंद्रों के माध्यम से जहां गंभीर चिकित्सा के नाम पर मरीजों को जानबूझकर वहां भेज कर एक तरफ शासन को चूना लगाते हैं तो दूसरी तरफ मरीजों को मानसिक और शारीरिक अनावश्यक कष्ट पहुंचा कर मोटी कमाई करते हैं।

बिशक ड्रग्स कांबिनेशन के नाम पर इस देश में लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी और निजी चिकित्सालयों में जनता से लगभग 10 लाख करोड रुपए लूट जाने के साथ-साथ सरकार को भी 10 लाख करोड रुपए से ज्यादा का चंदन लगाकर मोटी कमाई की जाती है सरकारी अस्पतालों का भी वही कमीशनखोरी की मोती कर प्रणाली है कि वह भी जानबूझकर मरीज को प्रदेश व कैंसर के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मान्य किए गए चिकित्सालय में भेज कर मोटी कमाई करती है जिसका मूल तांडव अपने कोरोना कल में देखा किस प्रकार से अकेले इंदौर में ही लगभग चिकित्सा के नाम पर मरीज को निजी चिकित्सालयों में भेज कर लगभग 2000 करोड़ का औषधीयों वह चिकित्सालय में भर्ती करने के नाम पर खेल किया गया इस खेल में चिकित्सकों के साथ इंदौर का डॉक्टर सेत्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्टर मनीष सिंह ने भी मोटी कमीशन खोरी की।

चिकित्सा सरकारी राज्य सरकारी ऑटोनॉमस संस्थान कहीं पर भी नौकरी करें और कितना भी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ले जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 20% है वह हरामखोर जलसा जिंदगी निजी चिकित्सा करने के साथ निजी चिकित्सालय में भी अपनी सेवाएं देकर मोटी कमाई करता है यथार्थ में अधिकांश में चिकित्सालय इन सरकारी डॉक्टर के अनुभव और ज्ञान के दम पर ही मोटे कमीशन पर चलाए जाते हैं वही हाल कर्मचारी राज्य बीमा सेवा में कार्यरत संचालक एवं संचालक सहायक संचालक स्तर के साथ 197 अन्य एमबीबीएस डिग्री डिप्लोमा और मास्टर्स की डिग्री के साथ 4 दंत चिकित्सक भी कार्यरत हैं 95% सब की अपनी निजी प्रेक्टिस है जबकि सभी 20% कुल वेतन कानॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी लेते हैं अधिकांश की चारों पांचों नगरों में अपनी निजी चिकित्सालय भी हैं।

वैसे भी डिस्पेंसिव को सुबह 8:00 से एक तक का समय और शाम को 4:00 से 7:00 बजे तक का समय होने के बाद में भी पूरे प्रदेश की डिस्पेंसियां अधिकांश शाम के समय बंद रहती हैं। इसके बारे में पूर्व में भी अनेकों समाचार पत्रों में छापा जा चुका है। सरकार पत्रकारों की तो फूल टाइप करती है कम से कम अपने ही विभाग के अधिकारियों डॉक्टरों इंजीनियरों के फोन टेप करके देखें कि वह कितना और कहां व कैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं?

भू कॉलोनी माफिया शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार का संरक्षक हैं कलेक्टर

पेज 8 का शेष

जो सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के इशारे व उनकी मोटे लाभ के लिए सारे सरकारी नियमों कानूनों को ताक पर रख, वृहत जनहितों को भूल, उनके हितों के लिए सारे वैध अवैध खेल करता रहता है।

स्वाभाविक सी बात है वह सबसे बड़ा भ्रष्ट और भ्रष्टाचार जालसाजों की लूट डकैती करने वालों का संरक्षण दाता भी होता है। इंदौर में जो भी कलेक्टर आता या पदस्थ किया जाता है। वह भू कॉलोनी शिक्षा परिवहन स्वास्थ्य आबकारी, कर, गुटका, औषधि, उद्योग, कृषि, माल्स, करचोर, पब होटल माफियाओं के इशारे पर सत्ताधीश दल के नेताओं के दानदाताओं के लिए ही प्रोजेक्ट किया जाता है स्वाभिक है। वह बरसों पुरानी कॉलोनीयों को कानूनों की आड़ में अवैध बताकर तोड़ेगा। तो जब वह कॉलोनी पर प्लांट बेंच रहा था नक्शे पास करवा रहा था कॉलोनी खड़ी करवा रहा था तब आपके पटवारी, राजस्व, निरीक्षक, उप तहसीलदार, तहसीलदार, सहायक उप व जिलाधीश के साथ निगम के राजस्व निरीक्षक, भवन निरीक्षक कॉलोनी सेल, उप, सहायक, कार्यपालन, अधीक्षण यंत्री, आंचलिक अधिकारी, सहायक उप व निगम आयुक्त वसूली लेकर क्यों चुप थे। तभी क्यों नहीं बताया जिन्होंने वहां प्लाट खरीद, मकान के नक्शे पास करवा और भवन बनाए थे। अब जब शहर में बड़े-बड़े राष्ट्रीय स्तर के भू व कॉलोनी माफिया भास्कर, ओमेक्स दीवान व अन्य कालोनियां काटने वाले डकैतों ने पूरे 42 किलोमीटर लंबे बाईपास, रिंग रोड पर, पिपल्याहाना, सुपर कॉरिडोर, धार, खंडवा, नेमावर, देवास, उज्जैन, कनाड़िया आदि मार्गों पर, अंबा मोलिया व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों कॉलोनाइजरों के मकान बिकवाने मोटा व्यवसाय करवाने मोटा कमीशन खाने के लिए शहर में बनी कॉलोनियों को या तो मोटा धन दो या अवैध सिद्ध कर तोड़ कर भय पैदा कर मोटी वसूली करेंगे। अभी हाल ही में इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने बोला की मध्य प्रदेश ग्रैंड मां मंडल द्वारा बनाई गई 1980 की नेहरू नगर एलआईसी की कॉलोनियों को कमजोर कर तोड़ने के लिए सबका बिजली पानी बंद करने के निर्देश नगर निगम इंदौर को दे दिए हैं जब भी कॉलोनी बन रही थी उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त और कार्यपालिका यांत्रियों से मोटा पैसा खाकर उन कॉलोनी को गुणवत्ताहीन बनाने की पूरी छूट दी थी दूसरी तरफ पिछले 40 सालों में उन कॉलोनियों का गृह निर्माण मंडल के उपायुक्त से लेकर कार्यपालन यंत्रियों सहायक और उप यंत्रियों ने सारा रख-रखाव मरम्मत का पैसा केवल कागज में खर्च कर करोड़ों रुपए हजम किया जब एक बार गृह निर्माण मंडल ने वहां के रवासियों को उन मकानों का पूरा पैसा वसूल कर लिया 20 साल से ज्यादा समय तक उसके पेट की रकम वसूल की और जब कॉलोनी फ्री होल्ड करके नगर निगम को सौंप दी तो आप उसका कौन सा कब्ज और कैसे जिले का कलेक्टर उन रहवासियों की तकलीफों को समझ दूर करने की अपेक्षा उनको तोड़ने की बात कर उन बेचारे बुजुर्गों को जिन्होंने अपनी जीवन भर की मेहनत की कमाई से एक छत की व्यवस्था की थी उनको हटाने भगाने के लिए और नई कॉलोनी के निर्माण में उसके टेंडर से लेकर निर्माण और भुगतान तक वैधानिक डकैतों और जालसाजो ने धन किसी पूंजीपति माफिया के साथ जिलों से लेकर प्रदेश भर में कार्य विभागों में कितना आवंटित धन में कहां से कमाया देश में और विदेश में कहां निवेश व खर्च किया। केंद्र व राज्य सरकारों के चुने हुए सत्ताधीशों को चाहिए, कीप वे इन देश के अभिलेख खुदाओं के संवैधानिक अधिकारों के पर कतर उन अधिकारियों की व्यवस्था करे। वैसे कलेक्टर आशीष सिंह को पदभार ग्रहण करने के साथ, सभी सरकारी कार्यालय व नगर निगम में मचे लूट भ्रष्टाचार के तांडव के साथ जनता को पूरे शहर में बार बार बनाई और डाली जाती नालियों खोदी जाती सड़कें बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था, निजी शिक्षा के मंदिरों, चिकित्सालयों में मचे लूट के तांडव को रोककर जनता को राहत दिलवाएं ताकि हमें भी कुछ अच्छा लिखने का मौका मिले।

इंदौर नगर निगम परिषद के दो साल पूरे

काम कम हुए... यू टर्न रहे ज्यादा...

शहर के चौराहों पर होर्डिंग लगाने का ठेका दिया गया। उसका भी विरोध हो गया तो चौराहों से होर्डिंग निकाले गए। रिमूवल गैंग को सेना जैसी वर्दी पहनाई गई। इसका भी जोरदार विरोध किया गया और वह फैसला भी रद्द करना पड़ा। पांच अगस्त को इंदौर नगर निगम के दो साल पूरे होने जा रहे है। इन दो सालों में बड़ी उपलब्धियां कम रही और यू टर्न ज्यादा रहे। भाजपा परिषद का दूसरा साल मेयर पुष्य मित्र भार्गव के लिए ज्यादा चुनौतियों भरा रहा। पोर्टल खराब होने के कारण राजस्व का काफी नुकसान हुआ। निगम ने शहर की जनता पर संपत्ति व जलकर का बोझ भी बढ़ा दिया। सफाई व्यवस्था भी अब कमतर हो गई है। 100 करोड़ के घोटाले के कारण भी निगम की साख गिरी।हुकमचंद मिल के मजदूरों के भुगतान, हरियाली में रिकार्ड जैसी उपलब्धियां भी रही।

सफाई व्यवस्था हो गई कमजोर

इंदौर के साथ पिछले साल सूरत शहर ने स्वच्छता रैंकिंग अवार्ड साझा किया था। इस साल पिछले साल की तुलना में सफाई व्यवस्था और कमजोर हो गई। शहर की बेकलेन ठीक से साफ नहीं हो पा रही है। इसके अलावा नालों में भी गंदगी ज्यादा है।

बदलना पड़े फैसले

नगर निगम परिषद द्वारा लिए गए कई फैसले भी बदलना पड़े। शहर के गांधी हॉल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की गई, लेकिन इसका विरोध हो गया और मामला ठंडे बस्ते में चले गए। शहर के चौराहों पर होर्डिंग लगाने का ठेका दिया गया। उसका भी विरोध हो गया तो चौराहों से होर्डिंग निकाले गए। रिमूवल गैंग को सेना जैसी वर्दी पहनाई गई। इसका भी जोरदार विरोध किया गया और वह फैसला भी रद्द करना पड़ा। शहर को सोलर सिटी बनाने की दिशा में भी सार्थक काम नहीं हुए। विधानसभा चुनाव के पहले शहर की आंतरिक सड़कों व पेयजल लाइन के काम जरुर कई क्षेत्रों में हुए।

अब कामों में आएगी तेजी

मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने कहा कि इस साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी। जो बड़े काम पिछले साल मंजूर हुए। वे अब गति पकडेंगे। जलूद में सोलर प्लांट का काम भी शुरू हो चुका है। सफाई व्यवस्था ठीक है। इस साल सफाई में अष्ठसिद्धि इंदौर को मिलेगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भ्रष्टाचार हर कदम कदम

सारडा, भदोरिया, भेषज दशौंधी 50:30:20

95% डॉक्टर करते हैं निजी प्रैक्टिस फिर भी लेते हैं वेतन का 20% भत्ता

मध्य प्रदेश के श्रम विभाग के अंतर्गत श्रमिकों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने वाला कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें भी केंद्रीय सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत कार्य करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली में देश के जाने-माने औषधि व चिकित्सा सामग्री निर्माता एवं आपूर्ति कर्ता

वहां बैठे संचालकों को मोटा पैसा खिला औषधीयों के और रासायनिक संयुक्त योगिकों जिनको बनाने की कला या निर्माता कुछ गिने-चुने ही होते हैं अपनी संयुक्त योगिक औषधियों यह कांबिनेशन ड्रग्स जो की चार गुना से 10 गुना ज्यादा तक महंगी होती है। मंजूरी करवा कर मान्य औषधि आपूर्ति कर्ताओं की सूची में शामिल करवा लेते हैं। फिर वही औषधि की आवश्यकता से 10 गुना ज्यादा तक की आपूर्ति जॉकी जिलों के केंद्र जिनके अंतर्गत छोटी डिस्पेंसरी काम करते हैं। जैसे इंदौर केंद्र के अंतर्गत 6 डिस्पेंसिव कम कर रही

हैं से औषधीय एवं चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति का दबाव देकर 10 गुना ज्यादा तक का इंडेंट या मांग पत्र मंगवाते हैं। फिरमध्य प्रदेश की और राज्य श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं में बैठे प्रभारी संचालक नटवर सारदा, प्रभारी सहायक संचालक अनिल भदौरिया वह 32 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठे भेषज या फार्मासिस्ट पंकज दसौंधी उसे मांग पत्र एजेंट के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम से मान्यता प्राप्त आपूर्ति कर्ताओं को ऐसी सभी कंबाइंड ड्रग्स व चिकित्सा सामग्री पर 40 से 60% कमीशन लेकर संबंधित जिले के केंद्र की डिस्पेंसरी को आदेश देकर औषधियां, इंजेक्शन, ट्यूब, बायल्स आदि की आपूर्ति करवाते हैं। शासकीय नियमों के अनुसार एक भैषज एक ही स्थान पर 3 वर्ष रह सकता है। परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यालय इंदौर की आपूर्ति में किसी कमीशन खोरी दलाली मैं सूत्रों के अनुसार 50: 30: 20 में संचालक सहायक संचालक और फार्मासिस्ट में बटवारा होता है। यही बटवारा प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, देवास में श्रमिकों की चिकित्सा के लिए डिस्पेंसरी के डॉक्टरों द्वारा ज्यादा गहन गंभीर चिकित्सा के लिए दिल्ली द्वारा स्वीकृत प्रदेश भर में 38 बड़े निजी डकैत चिकित्सालयों और अपने फर्जीवाड़े के लिए कुख्यात चिकित्सा महाविद्यालयों जहां पर आज भी न केवल विषय विशेषज्ञ डॉक्टरेट डीन, अच्छे अध्यापक, प्राध्यापक नहीं है। मैं भी चिकित्सा हेतु भेजा जाता है वहां पर भी मोती कमीशन खोरी होती है 2 दिन की चिकित्सा का 5 दिन का बिल बनता है। वही हाल औषधीय और खर्चे में भी 3 से 5 गुना का बिल मोटे कमीशन पर भेजा जाता है। उसे कमीशनखोरी में डिस्पेंसरियों के डॉक्टर से लेकर केंद्र और केंद्र से मुख्यालय तक सब की कमीशन खोरी होती है। इस बीमा चिकित्सा सेवा में बैठे मुख्यालय के चिकित्सकों से लेकर केंटो और डिस्पेंसरियों में बैठे चिकित्सक, फार्मासिस्ट तक जो आवश्यकता से 10 गुना अधिक मात्रा में औषधीयों इंजेक्शंस बॉयलस वह आनी चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति की जाकर भुगतान के दो द्वारा तो किया ही जाता है केंद्र में बैठे डॉक्टर भी अपना कमीशन वसूलते हैं इसके बाद में वह सामग्री जो डिस्पेंसरियों पर पहुंचाई जाती है। उसका मां चिकित्सा के आने लिए आने वाले श्रमिकों को 10 गुना ज्यादा देना व उपयोग दिखाकर बाजार में बेंच कर मोटा पैसा हजम कर लिया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिल्ली ऑफिस में मध्य प्रदेश में भोपाल में जिंदल हॉस्पिटल जहां हर प्रकार की जांच का रु. 3000 लगता है झांसी सिटी स्कैन इकोकार्डियोग्राफी स्कैनिंग व अन्य प्रकार की जांचों के रु. 3000 प्रति जांच में स्वभाविक बात है।

(शेष पेज 7 पर)

कानून बाप की जागीर नहीं, न ही आइएएस देश के खुदा

भू कॉलोनी माफिया शासकीय विभागों में भ्रष्टाचार का संरक्षक हैं कलेक्टर

भारत में अंग्रेजों ने नागरिक सेवा अधिकारी या सिविल सर्विसेज भारत के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गठित की थी। जिसकी बहुत ही कठिन परीक्षा होती थीऔर उसको उत्तीर्ण करने के बाद पूरे देश भर में जिलों संभागों के राजस्व या लगान एकत्रित करने व अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर जनता को हांकने, उनको प्रताड़ित करने उनके कानून ठोकने प्रशासन चलाने के लिए बनाई थी आजादी के बाद इन प्रशासनिक सेवा के उच्च शिक्षित व उच्च धूर्तों ने देखा की आजादी के बाद अंग्रेजों को जाने के कारण अभी यहां कोई खास नियम कानून आदि की कोई दमदार प्रणाली नहीं है।

इन हरामखोर उसका फायदा उठाकर अपने आप को और डकैत राजस्व कलेक्टर से प्रशासनिक अधिकारी बना देश के डकैत खुदा बन गए।

इनके लिए देश का कानून संविधान में पड़ी हुई उनकी रखैल है उनके अंतर्गत विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी बकरियां और जनता कीड़े-मकोड़े होती है। दिग्विजय सिंह की सत्ताकाल में ही इन जिलों के कलेक्टर को भी न केवल वैधानिक वरन अवैधानिक रूप से भी भू कॉलोनी उद्योग आपूर्ति स्वास्थ्य शिक्षा कृषि उद्यानिकी वन आदिम अनुसूचित जाति जनजाति खनन महिला बाल विकास, नगरीय प्रशासन नगर निगमों पालिकाओं परिषदों ग्रामीण विकास लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन, गृह निर्माण मंडल, निगम आयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी पालिकाओं परिषदों आदि मैं अधिकारियों को भ्रष्टाचार की

सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसके लिए भेड़ बकरियां, जनता कीड़े-मकोड़े, जब चाहे हजारों को बेघर करें, बिजली पानी बंद करें

खुली छूट दे उनके माफियाओं को पाल उनसे वसूली कर सरकारी धन के साथ सरकारी राजस्व में सैंध लगा कलेक्शन करके अपने आंखों को भोपाल में भी भेजना था स्वाभाविक सी बात थी जब रॉयल्टी व इएमआइ पर किसी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर एसपी आईजी डीजी कमिश्नर जिला कृषि, उद्यानिकी, खनन नागरिक आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, जल संसाधन, आदिम जाति जनजाति, आबकारी, परिवहन, बिजली पानी विभागों, आदि में धन लेकर पदस्थ किया जाएगा। तो वह तो भ्रष्टाचार से कमाये धन को बांटकर करेगा ही। फिर इंदौर तो सभी अधिकारियों की लूट की बड़ी प्रयोगशाला है जिले का कलेक्टर सबसे बड़ा शासकीय पदवी धारी घोर भ्रष्ट जालसाज डकैत अधिकारी होता है।

(शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958